



- अट्टारहवीं लोकसभा के लिए द्वीपों से निर्वाचित सदस्य बिष्णु पद रे ने कहा कि द्वीपों के लिए स्थानीय प्रमाणपत्र जारी कराने की दिशा में वे प्रयास करेंगे।
- अट्टारहवीं लोकसभा का पहला संसद सत्र चौबीस जून से शुरू हो रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इक्कीस जून को मनाया जाएगा।
- उत्तरी व मध्य अण्डमान ज़िला प्रशासन की ओर से डिगलीपुर में आए भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को वित्तीय सहायता वितरित किए गए।
- अंडमान निकोबार अग्नि और आपातकालीन सेवा में भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है।



अट्टारहवीं लोकसभा के लिए द्वीपों से निर्वाचित सदस्य बिष्णु पद रे ने कहा कि द्वीपों के लिए स्थानीय प्रमाणपत्र जारी कराने की दिशा में वे प्रयास करेंगे। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि वे द्वीपों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी ज्वलंत मुद्दों का समाधान कराने के लिए वे पुरजोर कोशिश करेंगे, ताकि द्वीपवासियों का कल्याण हो सके।



अट्टारहवीं लोकसभा का पहला संसद सत्र चौबीस जून से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि संसद के पहले सत्र में नव-निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव और फिर संसद के दोनों सदनों की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है।



अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इक्कीस जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आयुष की ओर से कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह पांच बजे से छः बजे और शाम चार बजे से पांच बजे तक आम जनता के लिए योगा हॉल आयुष अस्पताल, मरीना पार्क और जोगर्स पार्क में नियमित योगाभ्यास होगा। अट्टारह जून को सुबह साढ़े नौ बजे से जंगलीघाट चौराहे, गांधी प्रतिमा और भातुबस्ती बस स्टॉप पर पलेश मॉब तथा इक्कीस जून को सुबह साढ़े पांच बजे से द्वीपसमूह के छियालीस से अधिक केन्द्रों पर सामूहिक योग निदर्शन कार्यक्रम का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों के अलावा आयुष के योग निरीक्षकों द्वारा द्वीपों के विभिन्न देखभाल केन्द्रों में सामान्य योग प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।



दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन की ओर से प्रशासन आप के द्वार पहल के एक भाग के रूप में तहसीलदार अनुजा त्रिवेदी द्वारा एक न्यायिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के निरीक्षक एवं सभी संबंधित पटवारियों ने भाग लिया। शिविर में पच्चीस से अधिक म्युटेशन के मामलों का निपटान किया गया। इसके अलावा आम जनता के राजस्व संबंधी शिकायतों को भी सुना गया और यह आश्वासन दिया गया कि मामलों को शीघ्र निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। शिविर में कलीकट, प्रातरापुर, टेलराबाद, विम्बलीटान, गाराचरामा और बिड़नाबाद से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। ज़िला प्रशासन की ओर से म्युटेशन के मामलों को मौके पर ही निपटाने के लिए आने वाले दिनों में विभिन्न गांवों में ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे।



उत्तरी व मध्य अण्डमान ज़िला प्रशासन की ओर से कल डिगलीपुर स्थित प्रशासनिक भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्यारह जून को आए भारी बारिश और बाढ़ से हुए

नुकसान के लिए पीड़ितों को वित्तीय सहायता वितरित किए गए। इस अवसर पर सांसद बिष्णु पद रे मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने आपदा से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने की प्रयासों की भी सराहना की। गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत वित्तीय सहायता के मानदण्डों के अनुसार उपायुक्त उत्तरी व मध्य अण्डमान द्वारा पांच लाख सैंतीस हजार चार सौ अट्ठासी रूपए की राशि जारी की गई और एक सौ सत्रह बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में दो हजार पांच सौ से लेकर इक्कीस हजार रूपए तक की सहायता राशि जमा की गई। कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथि दिलखुश मीणा ने आपदा के दौरान उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आपातकालीन परिचालन केन्द्र तुरन्त सक्रिय हो गया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य शुरू हो गया। राहत आश्रय स्थल खोले गए और तुरन्त बाढ़ पीड़ितों को इन आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। बाढ़ के बाद एक क्षति मूल्यांकन समिति ने बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया। बैठक में सहायक आयुक्त डिगलीपुर आदित्य कुमार अस्थाना ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार अग्नि और आपातकालीन सेवा में भर्ती के लिए स्वीकृति प्राप्त हो गई है। दो हजार आठ से लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से इस बल में पुलिस सिपाही फायरमैन और पुलिस सिपाही ड्राइवर के पदों में भर्ती के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पुलिस सिपाही फायरमैन के इक्यावन और पुलिस सिपाही ड्राइवर के ग्यारह पदों को भरा जा सकेगा। इन पदों के भर जाने से बल की सेवाओं में और सुधार होगा।

<><><><><><>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में तीस सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता-प्राप्त संस्थानों, सम-विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू रहेगी। आयोग ने यह भी कहा कि इस वर्ष तीस सितंबर से इक्कीस अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम एक हजार रुपये की कटौती की जा सकेगी। इक्कीस अक्टूबर के बाद के दाखिले के लिए, अक्टूबर-दो हजार अठारह के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><>

क्षेत्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर आयुष मंत्रालय के तहत सी. सी. आर. ए. एस. की एक इकाई द्वारा अठारह जून से दो जुलाई तक डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ की एक टीम तेरेसा द्वीप में आदिवासी स्वास्थ्य रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम के तहत मुफ्त आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर आयोजन करेगी।

<><><><><><>

स्कूल ऑफ नर्सिंग में अल्प अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अंग्रेजी और कम्प्यूटर विषय के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पच्चीस जून को सुबह दस बजे से स्कूल ऑफ नर्सिंग में इसके लिए सीधे साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन इक्कीस जून की शाम तीन बजे तक जमा कर सकते हैं।

<><><><><><>